



19 मिनट	8	24	5 + 1	GS1 • 1	GS2 • 28	GS3 • 27
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	MCQS + MAINS	पेपर मिश्रण		

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 GST काउंसिल ने गिरफ्तारी की शक्तियों को खत्म किया और अभियोजन की सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी

क्यों जरूरी: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) बनाम टैक्स कंप्लायंस (Tax Compliance): GS3 और फिस्कल फेडरलिज्म (Fiscal Federalism) से संबंधित एक महत्वपूर्ण केस स्टडी।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

M

2 DGP नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, प्रकाश सिंह फैसले का होगा रिव्यू

क्यों जरूरी: तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के संबंध में एक शिकायत के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) राजू रामचंद्र को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या DGP की नियुक्तियों के लिए राज्य के नियम 2006 के प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन करते...

GS2 • राज्यव्यवस्था एवं संविधान

P

M

3 भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G यूजर बेस को बढ़ाकर एक बिलियन करना है

क्यों जरूरी: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी: GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण विषय।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

4 केंद्र सरकार ने नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन 30% तय किया

क्यों जरूरी: प्राइस कैपिंग और फार्मास्युटिकल रेगुलेशन: स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले व्यक्तिगत खर्च (out-of-pocket healthcare costs) को कम करने पर GS2 का एक केस स्टडी।

GS2 • सामाजिक न्याय

P

M

5 MeitY, AIKOSH रोडमैप के ज़रिए 10 मिलियन युवाओं को AI में ट्रेनिंग देगा

क्यों जरूरी: डिजिटल साक्षरता और AI गवर्नेंस: GS3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नैतिकता का एक केस स्टडी।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

आज का आँकड़ा

10 मिलियन

AI स्पेस में शामिल किए जाने वाले भारतीय युवाओं की लक्ष्य संख्या।

स्टैटिक से जोड़ें

RPwD एक्ट, 2016

यह टूल द्वारा पहचाने गए 21 विकलांगता स्थितियों (disability conditions) को परिभाषित करता है। खबर में: शिक्षा मंत्रालय ने 21 विकलांगता स्थितियों के लिए PRASHAST टूल का उपयोग करने हेतु 72 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।

GS3 · अर्थव्यवस्था

P

M

GST काउंसिल ने गिरफ्तारी की शक्तियों को खत्म किया और अभियोजन की सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी

चर्चा में क्यों: GST काउंसिल ने प्रवर्तन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को खत्म करने और अभियोजन की सीमा (prosecution threshold) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने को मंजूरी दी है।

याद रखें

- प्रोसिक्यूशन थ्रेशोल्ड (Prosecution threshold) — ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है।
- सामान्य दंड (General penalties) — ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिए गए।
- ऑफिसर्स की कमेटी — इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) सुरक्षा के अध्ययन के लिए तीन महीने के भीतर गठित।

मेन्स कोण वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रशासन में दंडात्मक प्रवर्तन से हटकर 'थ्रेशोल्ड-आधारित अभियोजन' (threshold-based prosecution) मॉडल की ओर बढ़ते बदलाव ने कर अनुपालन और 'व्यापार करने की सुगमता' (ease of doing business) के बीच संतुलन को किस प्रकार स्थापित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/132799

GS3 · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G यूजर बेस को बढ़ाकर एक बिलियन करना है

चर्चा में क्यों: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने 5G यूजर बेस को दोगुना करके एक बिलियन तक पहुँचाना है। साथ ही, उन्होंने साइबर फ्रॉड और डीपफेक्स (deepfakes) को रोकने के लिए GSMA के साथ एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की मांग की है।

याद रखें

- 2030 तक 5G यूजर बेस का लक्ष्य: 1 बिलियन।
- भारत 6G Alliance: 7,700 पेटेंट्स के साथ शामिल 90 संस्थान।
- GSMA: साइबर फ्रॉड और डीपफेक्स (deepfakes) के खिलाफ एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए वैश्विक संस्था से आह्वान।

मेन्स कोण 6G तकनीक के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व के महत्व और डीपफेक जैसे उभरते डिजिटल खतरों को कम करने के लिए एक वैश्विक ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/132623

GS2 · सामाजिक न्याय

P

M

केंद्र सरकार ने नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन 30% तय किया

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर रोगी दवाओं (non-scheduled anti-cancer drugs) पर ट्रेड मार्जिन को 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है, ताकि मरीजों के जेब से होने वाले खर्च (out-of-pocket costs) को कम किया जा सके, जो वर्तमान में 75% तक पहुँच जाता है।

याद रखें

- ट्रेड मार्जिन कैप: नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए अधिकतम रिटेल प्राइस (Maximum Retail Price) का 30%।
- अनुमानित वार्षिक बचत: आउट-ऑफ-पॉकेट (out-of-pocket) खर्चों में कमी से ₹2,500 करोड़।
- नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (National Pharmaceutical Pricing Authority): दवाओं की कीमतों में मार्क-अप (mark-ups) की पहचान करने के लिए जिम्मेदार संस्था।

मेन्स कोण आम आदमी के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक सस्ती पहुँच सुनिश्चित करने हेतु फार्मास्युटिकल व्यापार मार्जिन को विनियमित करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/132975

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

DGP नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, प्रकाश सिंह फैसले का होगा रिव्यू

चर्चा में क्यों: तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के संबंध में एक शिकायत के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) राजू रामचंद्र को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या DGP की नियुक्तियों के लिए राज्य के नियम 2006 के प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन करते हैं।

याद रखें

- राजू रामचंद्रन: DGP नियुक्ति नियमों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमिकस क्यूरी (amicus curiae) नियुक्त किए गए।
- प्रकाश सिंह जजमेंट: राज्य पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला 2006 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
- सुप्रीम कोर्ट: राज्य स्तर पर DGP की नियुक्ति के नियमों की वैधता की निगरानी करने वाली संस्था।

मेन्स कोण संस्थागत स्वायत्तता के सिद्धांतों के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति में राज्य सरकारों द्वारा एकपक्षीय विवेक का प्रयोग करने के संवैधानिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/132649

MeitY, AIKOSH रोडमैप के ज़रिए 10 मिलियन युवाओं को AI में ट्रेनिंग देगा

चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक्स (deepfakes) और मनोवैज्ञानिक विकारों जैसी समस्याओं से निपटने के लिए AI पर एक परामर्श पत्र (consultation paper) की घोषणा की है। साथ ही, उन्होंने 10 मिलियन भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए AIKOSH रोडमैप पर भी जोर दिया है।

याद रखें

- MeitY — इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology)।
- AIKOSH — युवाओं के लिए AI पहल से जुड़ा रोडमैप।
- 10 मिलियन — AI स्पेस में शामिल किए जाने वाले भारतीय युवाओं की लक्ष्य संख्या।

मेन्स कोण भारत में जनरेटिव एआई (Generative AI) प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न सामाजिक-मनोवैज्ञानिक जोखिमों को कम करते हुए, एआई-संचालित मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने की दोहरी चुनौती का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/132957

BBBP प्रोग्राम से बेहतर हुए नतीजे, हर 1,000 जन्म पर 15 लड़कियां बढ़ीं

चर्चा में क्यों: 'पॉलिसी इंटरवेंशन्स एंड द सेक्स रेशियो एट बर्थ: एविडेंस फ्रॉम इंडिया' (Policy Interventions and the Sex Ratio at Birth: Evidence from India) नामक एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 'बेटी बचाओ'

याद रखें

- BBBP डैशबोर्ड के अनुसार, भारत का जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratio at birth) 2015-16 में 919 से बढ़कर लगभग 930 हो गया है।
- BBBP प्रोग्राम ने शुरुआती जिलों में प्रति 1,000 जन्मों पर लगभग 15 अतिरिक्त लड़कियों को जोड़ा।
- गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और केरल में जन्म के समय सेक्स रेशियो (sex ratio at birth) सबसे अधिक दर्ज किया गया।

मेन्स कोण भारत में जन्म के समय लैंगिक असंतुलन की संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक हस्तक्षेप किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/132928

शिक्षा मंत्रालय ने 21 विकलांगता स्थितियों के लिए PRASHAST टूल का उपयोग करने हेतु 72 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया

चर्चा में क्यों: शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 21 विकलांगता स्थितियों की पहचान करने के लिए PRASHAST डिजिटल टूल का उपयोग करने हेतु 60,000 स्कूलों के 72 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।

याद रखें

- PRASHAST: 21 विकलांगता स्थितियों (disability conditions) की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक डिजिटल टूल।
- RPwD एक्ट, 2016: यह टूल द्वारा पहचाने गए 21 विकलांगता स्थितियों (disability conditions) को परिभाषित करता है।
- PM DAKSH: छात्रवृत्ति और डेटा इंटीग्रेशन (Data Integration) के लिए PRASHAST के साथ एकीकृत (Integrated)।

मेन्स कोण प्रशस्त (PRASHAST) जैसे डिजिटल पहचान उपकरणों का एकीकरण, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 के समावेशी शिक्षा के अधिदेश को किस प्रकार सुगम बनाता है? विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/132955

16th वित्त आयोग ने बड़े शहरी निकायों के लिए अर्बनाइजेशन प्रीमियम की सिफारिश की

चर्चा में क्यों: 16वें वित्त आयोग ने स्वच्छता और जल बुनियादी ढांचे (infrastructure) को समर्थन देने के लिए एक लाख से अधिक आबादी वाली शहरी स्थानीय निकायों (urban local bodies) के लिए एक बार मिलने वाले अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट (urbanization premium grant) की सिफारिश की है।

याद रखें

- अर्बनाइजेशन प्रीमियम (Urbanization premium) — एक लाख से अधिक आबादी वाले अर्बन लोकल बॉडीज (Urban Local Bodies) के लिए एक बार मिलने वाला ग्रांट।
- योग्यता मानदंड — ऑडिटेड आंकड़ों (audited figures) का प्रकाशन और 5% राजस्व वृद्धि।
- राज्य पात्रता — राज्यों के पास पिछले ग्रांट्स का कम से कम 20% वितरित (disbursed) होना अनिवार्य है।

मेन्स कोण स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों और शहरी स्थिरता की प्राप्ति में शहरी स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तांतरण के महत्व की चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/132737

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

फार्मा मार्केटिंग कोड को कानूनी रूप देने के लिए कमेटी बनाए सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मोचा पोर्ट ज़ब्त: हूथियों (Houthis) ने सितंबर में मोचा (Mocha) पर कब्जा कर लिया, जिससे बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य (Bab al-Mandeb strait) को खतरा पैदा हो गया और समुद्री सुरक्षा जोखिम बढ़ गए।

मतदाता सूची से नाम हटाना: विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान तेलंगाना की मतदाता सूची (electoral rolls) से लगभग 70 लाख मतदाताओं को स्थायी रूप से हटा दिया गया।

खुशी से सीखें: केरल की एक पहल जो सरकारी स्कूलों में एकेडमिक प्रेशर (academic pressure) और नशीली दवाओं के सेवन (substance abuse) के लिए काउंसलिंग प्रदान करती है।

करुणा हेल्थ स्कीम्स: केरल सरकार ने सामान्य कामकाज बहाल करने के लिए KASP और KBF के लंबित दावों को चुकाने हेतु ₹600 करोड़ से अधिक आवंटित किए हैं।

मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट: सगरमंथन 2026 के दौरान सऊदी अरब ने वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट और मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड (Maritime Development Fund) में अपनी रुचि व्यक्त की।

मौत की सजा कम करना: सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुझाव दिया है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने (commuting death sentences to life imprisonment) में अपनाई जाने वाली 'क्षमाशील प्रकृति' (forgiving nature) का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

यूनिवर्सिटी वित्त आयोग: केरल सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय स्थिरता और PPP मॉडल्स का मूल्यांकन करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया।

मतदाता पंजीकरण: महाराष्ट्र SEC ने ECI SIR प्रक्रिया की विसंगतियों को दूर करने के लिए विशेष कैंप और घर-घर सत्यापन (house-to-house verification) आयोजित किए।

भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज़: केरल रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अट्टापडी में SC, ST और फिशिंग कम्युनिटीज को 10,000 से अधिक टाइटल डीड्स (title deeds) जारी किए।

मानचित्र

चर्चा में स्थान

मोचा (Mocha) एक पोर्ट सिटी जिसे सितंबर में हूथिस (Houthis) ने कब्जे में ले लिया था।

बाब अल-मंडेब (Bab al-Mandeb) एक रणनीतिक जलडमरूमध्य (strait) जिस पर हूती गतिविधियों से खतरा है।

गैलेथिया बे (Galathea Bay) सऊदी अरब के निवेशकों के लिए रुचि का एक समुद्री प्रोजेक्ट साइट।

तीस्ता नदी इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड (landslides) और जमीन धंसने का स्रोत।

वीररंगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला 2,339 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है।

तमिलनाडु असेंबली प्रस्ताव: द हिंदू (The Hindu) के एडिटर्स को गिरफ्तार करने के 2003 के प्रस्ताव को 2004 में वापस ले लिया गया था, जिससे कानूनी चुनौती निष्प्रभावी (infructuous) हो गई।

भारत के सीजफायर प्रस्ताव को रूस ने किया रिजेक्ट, यूक्रेन युद्ध पर अपडेट

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

एशियाटिक शेर: जनसंख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक: दिल्ली हाई कोर्ट के वाइंडिंग ऑर्डर (winding order) के बाद, RBI ने PPBL को RBI Act, 1934 की Second Schedule से हटा दिया है।

रेपो रेट में बढ़ोतरी: RBI ने करेंसी की गिरावट और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% कर दिया।

वेस्टर्न घाट्स के नेचुरल हैबिटेट्स घटकर रह गए सिर्फ एक तिहाई

AI रेडीनेस इंडेक्स में भारत 10वें नंबर पर, 4.1 बिलियन डॉलर का निवेश

सैटेलाइट इंटरनेट: Starlink, Jio Satcom और Eutelsat OneWeb वर्तमान में गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लीयरेंस (security clearances) का इंतज़ार कर रहे हैं।

रेड लिस्ट असेसमेंट: केरल ने IUCN RLE फ्रेमवर्क का उपयोग करके 14 जिलों में पारिस्थितिक जोखिमों (ecological risks) का मानचित्रण करने के लिए दो साल का प्रोजेक्ट शुरू किया है।

PERM प्रोग्राम: US लेबर डिपार्टमेंट ने इंफोसिस, विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, टाटा, HCL और कैपजेमिनी के लिए PERM फाइलिंग को निलंबित कर दिया है।

नवीकरणीय ऊर्जा: आंध्र प्रदेश ने सोलर, विंड और पंपड स्टोरेज हाइड्रो सहित 97 प्रोजेक्ट्स के लिए ₹4 लाख करोड़ जुटाए।

हैदराबाद चर्चा में WHO की चेतावनी: स्किन-लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में मरकरी से सेहत को खतरा

NH10 अपग्रेड: टीस्ता नदी में भूस्खलन (landslides) से निपटने के लिए रंगपो से रानीपूल तक NH10 को अपग्रेड करने के लिए ₹993.64 करोड़ का प्रोजेक्ट।

नोबेल पुरस्कार: हेनरी कागन और केंजो सोई को साइड-इफेक्ट-फ्री फार्मास्यूटिकल्स (side-effect-free pharmaceuticals) को सक्षम बनाने के लिए केमिकल एसिमेट्री (chemical asymmetry) को हल करने के लिए सम्मानित किया गया।

- 1 नए GST काउंसिल गाइडलाइन्स के तहत जनरल पेनल्टी (General Penalties) के लिए कम की गई राशि क्या है?
 - a ₹5,000
 - b ₹20,000
 - c ₹15,000
 - d ₹10,000
- 2 भारत ने साइबर फ्रॉड और डीपफेक्स (deepfakes) को रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने हेतु किस वैश्विक संस्था (global body) से आह्वान किया?
 - a GSMA
 - b UNCTAD
 - c IEEE
 - d W3C
- 3 नोट के अनुसार, ड्रग प्राइसिंग में मार्क-अप्स की पहचान करने के लिए कौन सी बॉडी जिम्मेदार है?
 - a सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन
 - b ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया
 - c नेशनल हेल्थ अथॉरिटी
 - d नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी
- 4 भारतीय युवाओं को AI में प्रशिक्षित करने के लिए AIKOSH रोडमैप लॉन्च करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?
 - a इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - b विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 - c शिक्षा मंत्रालय
 - d कौशल विकास मंत्रालय
- 5 कौन सा एक्ट PRASHAST टूल द्वारा पहचाने गए 21 विकलांगता (disability) स्थितियों को परिभाषित करता है?
 - a विकलांगता अधिकार अधिनियम, 1995
 - b शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
 - c आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016
 - d नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020

मेन्स अभ्यास

आज एक उत्तर लिखें

GS3 • अर्थव्यवस्था

वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रशासन में दंडात्मक प्रवर्तन से हटकर 'थ्रेशोल्ड-आधारित अभियोजन' (threshold-based prosecution) मॉडल की ओर बढ़ते बदलाव ने कर अनुपालन और 'व्यापार करने की सुगमता' (ease of doing business) के बीच संतुलन को किस प्रकार स्थापित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।

(c) 5 (d) 4 (d) 3 (d) 2 (d) 1 • १९९



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

कोई गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक या फॉर्मेट चाहिए? हमें लिखें, हम हर मेल पढ़ते हैं:

contact@satyadheesh.in

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।